

# प्रातःकिरण

f /Pratahkiran

t /Pratahkiran

b /Pratahkiran

हर खबर पर पकड़

10 भारत में 2047 तक 47 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने का ...

वर्ष : 13

अंक : 281 | नई दिल्ली, गुरुवार, 23 फरवरी, 2023

पौष शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत् 2079

पेज : 12

मूल्य ₹ : 03.00

www.pratahkiran.com

इमरान की पीटीआई आज लाहौर से जेल भरो तहरीक की करेगी ... 12

एसी मानसिकता बनाई जा रही है कि जो 'जन्म से मृत्यु' तक का ठेकाले वही कल्याणकारी सरकार : वरुण गांधी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ वरुण गांधी ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक संघों ने मुक्त तरीकों से रेपकश का बढ़वा देकर जनमानस में एक ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित किया है कि जो सरकार जन से मृत्यु तक का उत्तम ठेका ले, वही कल्याणकारों द्वारा उत्तम ठेका ले जाएगा। असाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अक्सर अपनी चिंता जाता है कि जो एसी मानसिकता को रेपकश का पेशकश करते हैं और इसके वरुण गांधी ने कहा कि मुक्त कल्याणकारों की पेशकश कर सावधानिक

धन के व्यापक दुरुपयोग के बारे में संवाद की जरूरत है। गांधी ने अपनी हालिया किताब द इंडियन मेटेपोलिस के बारे में चर्चा करते हुए कहा, एसे कई बादे पूरे नहीं होते हैं या आशिक रूप से अपूरे रह जाते हैं। ऐसे बादे करना मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुक्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहए, यह देखते हुए कि यह मरे बच्चों के स्वास्थ्य को बदलने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि मुक्त उपहारों के लिए एक वित्त पोषण योजना प्रदान करने की एसी मानसिकता को एक जन्म से अंत तक कल्याणकारी सरकार है। उन्होंने कहा कि मुक्त उपहारों के इस दाखि में सुधार के लिए कई स्तर पर पहल की तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पैदा हो रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि हर योजना या घोषणा का बाद मुक्त नहीं है। उनके मुताबिक रक्खों में छात्रों के लिए मुफ्त भोजन, जैसा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसे मुक्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहए, यह देखते हुए कि यह मरे बच्चों के स्वास्थ्य को बदलने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि मुक्त उपहारों के लिए एक वित्त पोषण योजना प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए। संसद मजबूत करने और कार्य करने की जरूरत है। और उनके अमूर्त लालों के बारे में समझ के क्षमता बढ़ाने के लिए, योनियों को तैयार करने में सहायता के लिए एक बजटीय कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। शारीरों के सामने चुनौतियों के बारे में लिखाई अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हुए गांधी ने योजना बनाने की बात की गैरी ली, लेकिन हरित स्थानों को कमज़ोर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि और अब हर साल, मुंबई के कुछ सभसे महंगे रियल



आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश से तीन बार सासद रहे गांधी ने सुझाव दिया, मुक्त उपहारों की घोषणा करने वाली सरकारों (चाहे राज्य हो या केंद्र) को एक वित्त पोषण योजना प्रदान

करने की आवश्यकता होनी चाहिए। संसद मजबूत करने और कार्य करने की जरूरत है। उनकी विवादितों को तैयार करने में शहरीकरण के समर्थन में उन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया और कहा कि 1964 और 1991 में शहरीकरण की शहरीकरण की प्रक्रिया की धरती के विकास योजनाओं में 20 साल की अवधि के लिए एक बजटीय कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। शारीरों के सामने चुनौतियों के बारे में लिखाई अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हुए गांधी ने योजना बनाने में कई शहरी हरित स्थानों की आवश्यकता पर विचार करने में विफल रहे हैं। गांधी ने कहा, सरकारी स्तर पर, हम अपने शहरों में बांधों और ग्रीन जोन के मूल्य और उनके अमूर्त लालों के बारे में समझ के विवादितों को सामना कर रहे हैं। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया और कहा कि 1964 और 1991 में शहरीकरण की शहरीकरण की प्रक्रिया की धरती के विकास योजनाओं में 20 साल की अवधि के लिए एक बजटीय कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। शारीरों के सामने चुनौतियों के बारे में लिखाई अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हुए गांधी ने योजना बनाने की बात की गैरी ली, लेकिन हरित स्थानों को कमज़ोर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि और अब हर साल, मुंबई के कुछ सभसे महंगे रियल

एस्टेट ब्लैक मानसन की बारिश की बाढ़ में डूब जाते हैं। उन्होंने सिंगापुर के एक उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को इस बात पर पुरुषीर्वाचर करने की जरूरत है कि वह अपने शहरों का प्रबंधन कैसे करता है ताकि शहरीकरण की प्रक्रिया की धरती के विकास योजनाओं में 20 साल की अवधि के लिए बहतर बनाने पर जो दिया जाए। गांधी ने योजना बनाने में बुरी बातों की धूम राखा है, बोर्डिंग यार्डों में बुरी बातों की धूम राखा है, और अपनी पार्टी से स्वतंत्र रुख अपना रखे हैं। उन्होंने अब तक चार किताबें लिखी हैं।

## खाद्य सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती : जयशंकर

विदेश मंत्री ने कहा, मुझे अगर मौजूदा समय की कुछ बड़ी समस्या को चुनौता हो तो उन्हें अहम है खाद्य सुरक्षा का मामला। यूक्रेन युद्ध ने इस समस्या को और गहरा कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत एक खाद्य सुरक्षा का मामला हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध ने इस समस्या को और गहरा कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है। इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन से भी हम इस सन्देश को देना चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ज जरूरी है कि योजना बनाने की बात की गैरी ली जाए। यूक्रेन युद्ध से हम योजना बनाने की बात की गैरी ली है। इसके लिए

प्रातः किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा समय में विश्व की सबसे बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा का मामला है और इससे निर्दृष्टि के लिए सभी दोनों को मिलकर काम करना होगा। डॉ. जयशंकर ने मंगलवार को देर शाम श्रीनगर स्थित रेसे करशीरी कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश खोले जाने के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अधिकारी विवरण करते हुए यह बात कही।

विदेश मंत्री ने कहा, मुझे एक राष्ट्रीय राजनीति का काम नहीं होता है जो बुधवार को खाद्य सुरक्षा का मामला। यूक्रेन युद्ध ने इस समस्या को और गहरा कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत एक खाद्य सुरक्षा का मामला हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध ने इस समस्या को और गहरा कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है। इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन से भी हम इस सन्देश को देना चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ज जरूरी है कि योजना बनाने की बात की गैरी ली जाए। यूक्रेन युद्ध से हम योजना बनाने की बात की गैरी ली है। इसके लिए

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उससे जुड़ा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है। इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन से भी हम इस सन्देश को देना चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ज जरूरी है कि योजना बनाने की बात की गैरी ली जाए। यूक्रेन युद्ध से हम योजना बनाने की बात की गैरी ली है। इसके लिए

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उससे जुड़ा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का जो फैसला किया है वो बहुत अहम है। इसके परिणाम के बजल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है। इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन से भी हम इस सन्देश को देना चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ज जरूरी है कि योजना बनाने की बात की गैरी ली जाए। यूक्रेन युद्ध से हम योजना बनाने की बात की गैरी ली है। इसके लिए

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उससे जुड़ा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मानने का











## यूपी बजट 2023: योगी सरकार ने पेश किया मारी-भरकम बजट, पढ़ें बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं

लखनऊ, एजेंसी

योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट का आकार छह लाख 90 हजार दो से 42 करोड़ 40 लाख रुपये है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कृश्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है जिसना पर कोई नया करन नहीं लगाया गया फिर भी राजस्व को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कहा जनता को महागी से रहात देने के लिए देवोल-डीजल पर वैट कम किया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी धूमधारी किया गया है। यही कारण है कि आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा।

यहां पढ़ें बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं...

● प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए 3600 करोड़ रुपये देने का एलान।

● वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो को लिए 100 करोड़ रुपये का एलान।

● झारसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ रुपये का एलान।

● स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये खर्च का एलान।

● प्रदेश में फार्मा पाकों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये देने का एलान।

● प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जायें।

● लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापाना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिंडोर रीजनल रेपिड ट्रान्सिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्राप्ति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1306 करोड़ रुपये

की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल

कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए

मेडिकल कॉलेज कालेज स्थापित किए जायें।

● वाराणसी, गोरखपुर

व अन्य शहरों में मेट्रो रेल

परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● गोरखपुर नगर स्थित गोडगोद्धेश्वर नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्टन, डावर्जन एवं टीटीमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनाश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिधाना का विस्तार किया गया है।

● मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के स्थानांतर प्रसव की दस्ता में नियंत्रित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपये 1000 के चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की परिधानों को प्रसव की दस्ता में 6000 एकमुश्ति में दिये जाने का प्रवधान है।

● अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रवधान है।

● योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

● निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा

हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक व

बालिकाओं के लिये कक्षा 06 से कक्षा 12 तक

अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणीयों हैं। इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023-2024 से प्रारम्भ होने के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 15 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 2,50 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● मेरठ में योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना हेतु 25 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

● योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देना









